



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

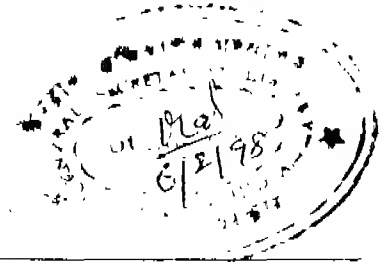
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 693]

नई दिल्ली, बुधस्वतियार, दिसम्बर 11, 1997/अग्रहायण 20, 1919

No. 693]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 1997/AGRAHAYANA 20, 1919

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1997

का.आ. 857(अ).—केन्द्रीय सरकार, यह अधिनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझती है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के अधीन किन आनुवंशिक और लघु औद्योगिक उपक्रमों को निम्नलिखित के लिए प्रभावकारी होने में जीवन क्षमता और सामर्थ्य बनाए रखने में समर्थ करने के लिए अनुपोषक उपायों, छूट या अन्य अनुकूल व्यवहार की आवश्यकता है :—

- (क) देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का सामंजस्य नीति से संवर्धन करना और बेकारी की समस्या को कम करना, और
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ।

और प्ररूप अधिसूचना को, उक्त अधिनियम की धारा 11 ख की उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित तीस दिन की अवधि के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया था ।

और संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तावित अधिसूचना में किसी उपांतरण का सुझाव नहीं दिया गया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11ख की उपधारा (1) और धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 232(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1991 को अधिकृत करते हुए, निम्नलिखित तथ्यों को विनिर्दिष्ट करती है, जिनके आधार पर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम को लघु उद्योग या आनुवंशिक औद्योगिक उपक्रम माना जाएगा :—

- (1) लघु औद्योगिक उपक्रम कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में नियम आस्तियों में विनिधान चाहे यह स्वामित्व निबन्धनों या पट्टे पर या किराया क्रय पर धारित हो तीन करोड़ रुपये से अधिक नहीं है,

- (2) आनुवंशिक औद्योगिक उपक्रम—ऐसा कोई औद्योगिक उपक्रम, जो पुर्जों, संघटकों उप आसंजकों, औजारों या मध्यवर्तियों का विनिर्माण करता है या विनिर्माण करना चाहता है या सेवाएं प्रदान कर रहा है या करना चाहता है और आपूर्ति कर रहा है या आपूर्ति करना चाहता है या अपने उत्पादन या सेवाओं का पचास प्रतिशत से अनधिक, यथास्थिति, ऐसे एक या अधिक अन्य औद्योगिक उपक्रमों को, प्रदान करता है या करना चाहता है, जिसकी संयंत्र और मशीनरी में नियम आस्तियों में, चाहे स्वामित्व निबन्धनों पर या पट्टे पर या किराया क्रय पर धारित हो, विनिधान तीन करोड़ रुपये से अधिक नहीं है,

टिप्पण 1.— ऊपर निर्दिष्ट कोई लघु उद्योग, या आनुवंशिक औद्योगिक उपक्रम किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम या समानुवंशिक या उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :

इस टिप्पण के प्रयोजनों के लिए—

- (क) “स्वामित्व प्राप्त” का वही अर्थ हो जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड (च) में विनिर्दिष्ट पद “स्वामी” की परिभाषा से व्युत्पन्न होगा।
- (ख) “समनुवंशी” का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 के साथ पठित धारा 2 के खंड (47) में है।
- (ग) “किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा नियंत्रित” पद का अर्थ निम्नलिखित होगा, अर्थात् :—
- (1) जहां एक ही व्यक्ति द्वारा स्वतन्त्राधीन के रूप में, दो या अधिक औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए गए हैं वहां, ऐसे प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम को अन्य औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों द्वारा नियंत्रित समझा जाएगा,
 - (2) जहां, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 1) के अधीन भागीदारी फर्म के रूप में दो या अधिक औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए गए हैं, और ऐसी फर्म में एक या अधिक भागीदार सामान्य भागीदार है, वहां ऐसे प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम को अन्य औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों द्वारा नियंत्रित समझा जाएगा,
 - (3) जहां, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन कंपनियों द्वारा औद्योगिक उपक्रम स्थापित किए गए हैं, वहां कोई औद्योगिक उपक्रम, किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा नियंत्रित समझा जाएगा, यदि—
 - (क) अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा धारित साम्या इसके कुल साम्या के 24 प्रतिशत से अधिक हों, या
 - (ख) किसी उपक्रम का प्रबंध नियंत्रण, किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि पहले उल्लिखित उपक्रम का प्रबंध निदेशक अन्य उपक्रम का भी प्रबंध निदेशक या निदेशक है अथवा पहले उल्लिखित उपक्रम के बोर्ड पर निदेशकों की बहुमत उपखंड (iv) के निम्नलिखित मद (क) और (ख) के उपबंधों के अनुसार अन्य औद्योगिक उपक्रम में साम्या धारक हैं,
 - (4) उपखंड (iii) के अनुसार किसी उपक्रम के साम्या में अन्य औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों द्वारा भाग लेने की सीमा निम्न प्रकार से तय की जाएगी :—
 - (क) अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा साम्या में भाग लेने के अंतर्गत विदेशी और देशी, दोनों साम्या सम्मिलित हैं,
 - (ख) अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा साम्या में भाग लेने से अभिप्रेत है अन्य औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों द्वारा, चाहे वे लघु अथवा अन्यथा हों, किसी औद्योगिक उपक्रम में, धारित कुल साम्या, इसमें उन व्यक्तियों के साम्या भी सम्मिलित होंगे, जो किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों में निदेशक हैं चाहे वह सम्बद्ध व्यक्ति किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों में निदेशक हों,
 - (ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित साम्या जिसके पास विशेष तकनीकी अर्हता और अनुभव है और जिसे किसी लघु औद्योगिक उपक्रमों में निदेशक नियुक्त किया गया है, यदि संगम के अनुच्छेदों में यह उपबंधित है, तो अर्हता शेषों की सीमा तक, अन्य औद्योगिक उपक्रम या उपक्रम द्वारा धारित साम्या की संगणना में, नहीं लिए जाएंगे चाहे वह संबद्ध व्यक्ति किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों में निदेशक हों,
 - (5) जहां कोई औद्योगिक उपक्रम उपखंड (1), उपखंड (2) या उपखंड (3) के अनुसार किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम या उपक्रमों की समनुवंशी है या उसके/उनके द्वारा स्वामित्व प्राप्त अथवा नियंत्रित है, और यदि पहले उल्लिखित औद्योगिक उपक्रम तथा अन्य औद्योगिक

उपक्रम या उपक्रमों के संबंध और मशीनरी में स्थिर आस्तियों में कुल विनिधान, इकट्ठा किए जाने पर, यथास्थिति, इस अधिसूचना के पैरा (1) या पैरा (2) में विनिर्दिष्ट विनिधान से अधिक हो जाता है, तो इनमें से किसी भी औद्योगिक उपक्रम को लघु या आनुवंशिक औद्योगिक उपक्रम नहीं समझा जाएगा।

टिप्पण : 2—

- (क) इस अधिसूचना के पैरा (1) और पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की संगणना करने में, इस बात को विचार में लिए बिना कि संयंत्र और मशीनरी नए हैं या बरते हुए हैं, उनकी मूल कीमत को हिसाब में लिया जायेगा।
- (ख) संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की संगणना करते समय निम्नलिखित को अपवर्जित किया जाएगा, अर्थात्:—
 - (i) अनुरक्षण के लिए उपस्करों, जैसे औजारों, जिंग, डाई, सांचे और अतिरिक्त पुर्जों की लागत तथा खपने वाले समान की लागत,
 - (ii) संयंत्र और मशीनरी की संस्थापन लागत;
 - (iii) अनुसंधान और विकास उपस्कर और प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों की लागत;
 - (iv) राज्य विद्युत् बोर्ड के विनियमों के अनुसार उपक्रम द्वारा संस्थापित उत्पादन सेटों और अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों आदि की लागत;
 - (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या राज्य लघु उद्योग निगम को संदत्त बैंक प्रभार और सेवा प्रभार;
 - (vi) केबल, वायरिंग, बस बार, विद्युत् नियंत्रण पेनल (उनसे भिन्न जो अलग-अलग मशीनों पर मंडे हुए हैं), आयल सर्किट ब्रेकर या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, को उपाप्त करने या संस्थापित करने में अर्न्तवर्तित लागत, जो संयंत्र और मशीनरी या सुरक्षा उपयों को विद्युत् शक्ति उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक रूप से प्रयोग की जानी है;
 - (vii) गैस उत्पादन संयंत्र की लागत;
 - (viii) स्वदेशी मशीनरी के लिए विनिर्माण स्थान से कारखाना स्थल तक परिवहन प्रभार (विक्रय कर और उत्पाद शुल्क को छोड़कर);
 - (ix) संयंत्र और मशीनरी के परिनिर्माण की तकनीकी जानकारी के लिए संदत्त प्रभार;
 - (x) ऐसे भंडारण टैकों की लागत जिनमें केवल कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद का भंडार रहता है और जो विनिर्माण से जुड़े नहीं हैं, और
 - (xi) अग्नि शमन उपस्करों की लागत।
- (ग) आयातित मशीनरी की दशा में, मूल्य की संगणना करते समय निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात्:—
 - (i) आयात शुल्क (प्रकीर्ण व्यय, जैसे पत्तन से कारखाना स्थल तक परिवहन व्यय, पत्तन पर संदत्त डेमेरेज को छोड़कर);
 - (ii) पोत परिवहन प्रभार;
 - (iii) सीमा शुल्क निकासी प्रभार;
 - (iv) विक्रय कर।

प्रत्येक वह औद्योगिक उपक्रम, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या उक्त अधिनियम की धारा 11, धारा 11क और धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई है और अनुषंगी या लघु उद्योग उपक्रम से संबंधित पैरा (1) और पैरा (2) के उपबंधों में आते हैं, को स्वामी के विवेकानुसार राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर, इस रूप में, रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 10/6/97-आई.पी.]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY**(Department of industrial Policy and Promotion)****ORDER**

New Delhi, the 10th December, 1997

S.O. 857(E).— Whereas the Central Government considers it necessary with a view to ascertain which ancillary and small scale industrial undertakings need supportive measures, exemption or other favourable treatment under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (herein after referred to as the said Act) to enable them to maintain their viability and strength so as to be effective in-

- (a) promoting in a harmonious manner the industrial economy of the country and easing the problem of unemployment, and
- (b) securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

And whereas the draft notification was laid before each House of Parliament for a period of thirty days as required under sub-section (3) of section 11B of the said Act;

And whereas no modification in the proposed notification has been suggested by both the Houses of Parliament;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11B and sub-section (1) of section 29B of the said Act, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) number S.O.232(E), dated the 2nd April, 1991, the Central Government hereby specifies the following factors on the basis of which an industrial undertaking shall be regarded as a small scale or as an ancillary industrial undertaking for the purposes of the said Act:-

(1) **Small scale industrial undertaking:** An industrial undertaking in which the investment in fixed assets in plant and machinery, whether held on ownership terms or on lease or on hire purchase, does not exceed rupees three crores;

(2) **Ancillary industrial undertaking:** An industrial undertaking which is engaged or is proposed to be engaged in the manufacturing or production of parts, components, sub-assemblies, tooling or intermediates, or the rendering of services, and undertaking supplies or proposes to supply or renders not more than fifty per cent of its production or services, as the case may be, to one or more other industrial undertakings and whose investment in fixed assets in plant and machinery, whether held on ownership terms or on lease or on hire purchase, does not exceed rupees three crores

Note 1- No small scale or ancillary industrial undertaking referred to above shall be subsidiary of, or owned or controlled by any other industrial undertaking.

Explanation- For the purposes of this note, -

(A) “owned” shall have the meaning as derived from the definition of the expression “owner” specified in clause (f) of section 3 of the said Act;

(B) “subsidiary” shall have the same meaning as in clause (47) of section 2, read with section 4, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(C) the expression “controlled by any other industrial undertaking” means as under:-

(i) where two or more industrial undertakings are set up by the same person as a proprietor, each of such industrial undertakings shall be considered to be controlled by the other industrial undertaking or undertakings,

(ii) where two or more industrial undertakings are set up as partnership firms under the Indian Partnership Act, 1932 (1 of 1932) and one or more partners are common partner or partners in such firms, each such undertaking shall be considered to be controlled by the other undertaking or undertakings,

(iii) where industrial undertakings are set up by companies under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), an industrial undertaking shall be considered to be

controlled by other industrial undertaking if,-

- (a) the equity holding by other industrial undertaking in it exceeds twenty four per cent of its total equity; or
- (b) the management control of an undertaking is passed on to the other industrial undertaking by way of the Managing Director of the first mentioned undertaking being also the Managing Director or Director in the other industrial undertaking or the majority of Directors on the Board of the first mentioned undertaking being the equity holders in the other industrial undertaking in terms of the provisions of the following items(a) and (b) of sub-clause (iv);
- (iv) the extent of equity participation by other industrial undertaking or undertakings in the undertaking as per sub-clause (iii) above shall be worked out as follows:-

- (a) the equity participation by other industrial undertaking shall include both foreign and domestic equity;
- (b) equity participation by other industrial undertaking shall mean total equity held in an industrial undertaking by other industrial undertaking or undertakings, whether small scale or otherwise, put together as well as the equity held by persons who are Directors in any other industrial undertaking or undertakings even if the person concerned is a Director in other Industrial Undertaking or Undertakings;
- (c) equity held by a person, having special technical qualification and experience, appointed as a Director in a small scale industrial undertaking, to the extent of qualification shares, if so provided in the Articles of Association, shall not be counted in computing the equity held by other industrial undertaking or undertakings even if the person concerned is a Director in other industrial undertaking or undertakings;

(v) where an industrial undertaking is a subsidiary of, or is owned or controlled by, any other industrial undertaking or undertakings in terms of sub-clauses(i); (ii); or (iii) and if the total investment in fixed assets in plant and machinery of the first mentioned industrial undertaking and the other industrial undertaking or undertakings clubbed together exceeds the limit of investment specified in paragraphs

(1) or (2) of this notification as the case may be, none of these industrial undertakings shall be considered to be a small scale or ancillary industrial undertaking.

Note 2- (a) In calculating the value of plant and machinery for the purposes of paragraphs (1) and (2) of this notification, the original price thereof, irrespective of whether the plant and machinery are new or second hand, shall be taken into account.

(b) In calculating the value of plant and machinery, the following shall be excluded, namely:-

- (i) the cost of equipments such as tools, jigs, dies, moulds and spare parts for maintenance and the cost of consumable stores;
- (ii) the cost of installation of plant and machinery;
- (iii) the cost of research and development equipment and pollution control equipment;
- (iv) the cost of generation sets and extra transformer installed by the undertaking as per the regulations of the State Electricity Board;
- (v) the bank charges and service charges paid to the National Small Industries Corporation or the State Small Industries Corporation;
- (vi) the cost involved in procurement or installation of cables, wiring, bus bars, electrical control panels (not those mounted on individual machines), oil circuit breakers or miniature circuit breakers which are necessarily to be used for providing electrical power to the plant and machinery or for safety measures;
- (vii) the cost of gas producer plants;
- (viii) transportation charges (excluding of sales-tax and excise) for indigenous machinery from the place of manufacturing to the site of the factory;
- (ix) charges paid for technical know-how for erection of plant and machinery;

- (x) cost of such storage tanks which store raw materials, finished products only and are not linked with the manufacturing process; and
 - (xi) cost of fire fighting equipments.
- (c) In the case of imported machinery, the following shall be included in calculating the value, namely :-
- (i) import duty (excluding miscellaneous expenses as transportation from the port to the site of the factory, demurrage paid at the port);
 - (ii) the shipping charges;
 - (iii) customs clearance charges; and
 - (iv) sales tax.

Every industrial undertaking which has been issued a certificate of registration under section 10 of the said Act or a license under sections 11, 11A and 13 of the said Act by the Central Government and are covered by the provisions of paragraphs (1) and (2) above relating to the ancillary or small scale industrial undertaking, may be registered, at the discretion of the owner, as such, within a period of one hundred and eighty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 10/6/97-IP]
ASHOK KUMAR, Jt. Secy.